

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संपादित
प्रतिलेख: 5 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामिनाथन जे - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री शिरीष चंद्र मुर्मू - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री इंद्रनील भट्टाचार्य - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री संजय कुमार हांसदा - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक:

श्री ब्रिज राज - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

ब्रिज राज:

सभी को नमस्कार। नीति की घोषणा के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पाँचवीं है। हमारे साथ हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे, डॉ. पूनम गुप्ता और पहली बार श्री शिरीष चंद्र मुर्मू। आज हमारे साथ कार्यपालक निदेशक भी हैं, डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी, श्री इंद्रनील भट्टाचार्य और पहली बार श्री संजय कुमार हांसदा। मैं रिज़र्व बैंक के अपने अन्य सहयोगियों का भी स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले, हमारे पास कुछ ज़रूरी घोषणाएँ हैं।

सर, मीडिया से 26 प्रतिभागी हैं। मैं मीडिया प्रतिभागियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे एक ही सवाल पूछें ताकि सभी को मौका मिल सके। मैं सभी से यह भी अनुरोध करूँगा कि बोलते समय अपना माइक चालू रखें ताकि जो लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं, वे साफ़-साफ़ सुन सकें। और जब आप बोलना समाप्त कर लें, तो कृपया माइक बंद कर दें। सर, आपकी अनुमति से, अब मैं नाम पुकारूँगा।

धन्यवाद सर। मैं सीएनबीसी-टीवी 18 की सुश्री लता वेंकटेश से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे पहला सवाल पूछें।

लता वेंकटेश: धन्यवाद, श्री ब्रिज राज।

संजय मल्होत्रा: आप ओपनिंग बैट्सवुमन हैं।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी 18:

ओपनिंग बैटर, आजकल सभी मुझे यही कहते हैं। गवर्नर साहब, मैं महंगाई के अनुमान से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आपने इसे पहले की दो नीति के मुकाबले कम किया है। आपने अगले साल की पहली तिमाही (ति1) के लिए 4.9 का अनुमान लगाया था, अब इसके साथ, अनुमान 3.9 है, और फिर अगली तिमाही के लिए 4.0 है। साथ ही, आप कह रहे हैं कि अगर सोने को हटा दिया जाए, तो यह 50 आधार अंक कम होगा। क्या आप कहेंगे कि इससे एमपीसी को विकास को समर्थन देने के लिए और गुंजाइश मिलती है? और अगर आप हमें करेंसी पर भी अपनी टिप्पणी दे सकें, तो क्या आपको लगता है कि इसका मूल्यांकन कम किया गया था? करेंसी को लेकर आरबीआई का क्या दृष्टिकोण है?

संजय मल्होत्रा:

तो, दो सवाल। क्या आगे और गुंजाइश है? आज हम न्यूट्रल (तटस्थ) स्थिति में हैं। हमारा मानना है कि जैसा कि आपने भी इशारा किया है और जैसा मैंने अपने भाषण और अपने आकलन में बताया है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि महंगाई बहुत ही नरम है। यह नरम ही रही है, 3.0-3.5%। अगर आप खाने-पीने की चीज़ों को हटा दें, जिनमें उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहता है, तो पिछले दो सालों में यह 3.0-3.5% रही है। और आगे भी, अगर आप सोना और कीमती धातुएँ, जैसे चाँदी, को हटा दें, तो हमारी उम्मीद है कि यह बहुत ही नरम रहेगी।

अब, क्या इससे आगे और दर में कटौती की गुंजाइश बनती है, यह तो महज अटकलबाज़ी होगी। मैं इस सवाल में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए, अब ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक और कम करने के बाद, अब हमें मौद्रिक नीति के प्रसार पर ध्यान देना होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई बहुत ही नरम रहने वाली है, मेरा मानना है कि पहले इसे असली अर्थव्यवस्था तक पहुँचने दिया जाए। और फिर हम देखेंगे कि महंगाई का रुख कैसा रहता है, विकास-महंगाई का तालमेल कैसा रहता है। और हम हर नीति पर अलग से फ़ैसला लेते हैं।

दूसरा सवाल रुपये पर। देखिए, हमारी घोषित नीति हमेशा से यही रही है कि हम बाज़ार को ही तय करने देते हैं। मेरा मतलब है कि हम किसी खास कीमत या किसी दायरे को लक्ष्य नहीं करते। हम बाज़ार को ही कीमतें तय करने देते हैं। हमारा मानना है कि लंबे समय में, खासकर, बाज़ार बहुत ही कुशल होते हैं। यह एक बहुत ही गहरा बाज़ार है। हमने यह पहले फरवरी में देखा था, जब रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 88 तक पहुँच गया था। और तीन महीनों के अंदर ही, यह वापस 84 से नीचे आ गया। तो, ये

उतार-चढ़ाव, यह अस्थिरता होती रहती है, हो सकती है। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि किसी भी असामान्य या बहुत ज़्यादा अस्थिरता को कम किया जाए। और हम आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे।

हमारा बाहरी क्षेत्र, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया था, आगे चलकर बहुत मज़बूत रहने वाला है। हमारा पूरा मानना है कि हमारे पास पर्याप्त रिज़र्व हैं। चालू खाता भी संभालने की स्थिति में है, लगभग 1% के आस-पास। और हमारे देश के मज़बूत बुनियादी आधार को देखते हुए, आगे भी हमें अच्छा पूंजी प्रवाह मिलना चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक बाह्य क्षेत्र की स्थिति का सवाल है, हम बहुत ही सहज स्थिति में हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। यहाँ आने से पहले हम बाईं ओर से कुछ और सवाल लेंगे।

तो, अगले सवाल के लिए, मैं टाइम्स ऑफ़ इंडिया के श्री मयूर शेट्टी से पूछूँगा।
मयूर, कृपया।

मयूर शेट्टी, टाइम्स ऑफ़ इंडिया:

धन्यवाद, गवर्नर। ऐतिहासिक रूप से, लगभग 2% का चालू खाता घाटा संभालने लायक माना जाता था क्योंकि हमारे पास ये पूंजी प्रवाह थे। लेकिन अब जब ये फ़्लो कम हो रहे हैं, तो क्या आपके नज़रिए में कोई बदलाव आया है कि क्या चीज़ संभालने लायक है?

क्या यह मौजूदा स्तर के आस-पास है? और सवाल का दूसरा हिस्सा यह था कि, रुपये में हाल की अस्थिरता के बावजूद आपने दरें कम कर दीं। और कई अनुमान लगाने वालों ने अपनी उम्मीदों में बदलाव किया है। तो, क्या यह विदेशी मुद्रा बाज़ार की स्थिति को लेकर आपके भरोसे को दिखाता है?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक एमपीसी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, एमपीसी मुख्य रूप से विकास-मुद्रास्फीति के समीकरणों से चलती है, खासकर इस बात को देखते हुए कि हमारी अर्थव्यवस्था घरेलू माँग पर आधारित है। मेरा मतलब है कि बाहरी क्षेत्र पर हमारी निर्भरता, हमारी कुल जीडीपी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए, हम ऐसा करना जारी रखते हैं। और इसीलिए हालाँकि एमपीसी इन कारकों पर ज़रूर विचार करती है, लेकिन विकास-मुद्रास्फीति के समीकरणों को देखते हुए, यह फ़ैसला लिया गया। आपके पहले सवाल के बारे में, मुझे लगता है कि लता के पहले

सवाल के जवाब में मैंने जो कहा था, उसमें मुझे और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है; यानी कि हम बहुत ही सहज स्थिति में हैं... मुझे उम्मीद नहीं है कि सीएडी 2% जितना ऊँचा जाएगा। जैसा कि आप कुछ आँकड़े बता रहे हैं। और इसलिए, बाह्य क्षेत्र के मामले में, हम बहुत ही सहज स्थिति में हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ के अंकुर मिश्रा से अगला सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा।

अंकुर, प्लीज़।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

इस मौके के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गवर्नर साहब। मैं इस बार विकास के अनुमान में हुए बदलाव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने इसे ऊपर की ओर संशोधित किया है। हालाँकि, सरप्राइज़ हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन पिछले दो तिमाहियों में विकास दर आरबीआई के अनुमान से कहीं ज़्यादा रही है। इसलिए, मैं यह समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या वजहें रही हैं? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पिछली बार जब मैंने आपसे हमारी आकांक्षाओं के बारे में सवाल पूछा था, तो आपने कहा था कि हमारी आकांक्षा 7% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब आपने 7% से ज़्यादा, यानी 7.3% का अनुमान लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी आकांक्षा अब 8% की ओर बढ़नी चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

तो, आप 9% भी कह सकते थे। 7% से ज़्यादा का मतलब कुछ भी हो सकता है, है ना? तो वह एक बेसलाइन है। जब मैंने 7% कहा था, तो वह असल में एक बेसलाइन ही थी। क्योंकि यह अनुमान लगाना कि हमारी संभावित जीडीपी कितनी हो सकती है, एक मुश्किल काम है। बेशक, हमारी आकांक्षाएँ बहुत ऊँची हो सकती हैं। और इसलिए, पिछले 3-4 सालों में औसतन 8% की विकास हासिल करने के बाद, यह निश्चित रूप से हमारी पहुँच में है और हमें निश्चित रूप से उस दायरे में आने वाली किसी भी विकास के लिए कोशिश करनी चाहिए।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं ब्लूमबर्ग के अनूप राँय से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा। अनूप, प्लीज़।

अनूप राँय, ब्लूमबर्ग:

इस मौके के लिए धन्यवाद। सर, बाज़ार इस नीति में रुपये से जुड़े कुछ उपायों की उम्मीद कर रहे थे। और अक्टूबर में, हमने देखा था कि आरबीआई शायद बड़े पैमाने पर दखल दे रहा था, लेकिन फिर उसने दखल देना बंद कर दिया और उसके बाद रुपया तेज़ी से 90 के स्तर पर पहुँच गया। तो, क्या आप रुपये के इस स्तर से सहज हैं?

संजय मल्होत्रा:

मेरे पास इसमें जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास अब और कोई सवाल नहीं हैं।

अनूप राँय:

सर, तो फिर मैं यह पूछना चाहूँगा कि इस संदर्भ में डॉलर-रुपया स्वैप किस तरह मदद करते हैं? क्योंकि यह पैसे डाल नहीं रहा है...

संजय मल्होत्रा:

यह ज़्यादातर चलनिधि का एक उपाय है। यह रुपये को सहारा देने के लिए नहीं है। और आपके पहले सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि हम किसी भी स्तर को लक्ष्य नहीं करते, चाहे स्तर कोई भी हो। इसलिए, हम किसी भी स्तर को लक्ष्य नहीं करते और हम बस रुपये को उसकी सही स्थिति, सही स्तर और दायरे में आने देते हैं, ताकि उसकी घट-बढ़ व्यवस्थित रहे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं मनी कंट्रोल की हमसिनी कार्तिक से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा। हमसिनी, प्लीज़।

हमसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद, सर। नमस्कार सर। क्रेडिट विकास के मामले में बैंकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? आम तौर पर, पैमाना यह होता है कि क्रेडिट विकास जीडीपी से दोगुना (2x) होता है। हम आम तौर पर इसी अंदाज़े के साथ काम करते हैं, है ना? लेकिन अब जीडीपी का अंदाज़ा 8% के आसपास है, जबकि क्रेडिट विकास सिर्फ 11% के आसपास है। और वह संख्या क्या है? आपने अब काफ़ी 'फ्रंट लोडिंग' की है, रेपो दर में 125 आधार अंक की कटौती की है। इसका असर (ट्रांसमिशन) भी काफ़ी अच्छा रहा है, पिछले चक्र की तुलना में ज़्यादा बेहतर। बैंकों के लिए आपका क्या संदेश होगा?

और क्रेडिट विकास के मामले में वह 'जादुई संख्या' क्या है जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी?

संजय मल्होत्रा:

मुझे नहीं पता कि आपको क्रेडिट-टू-जीडीपी विकास दर का यह 'दोगुना' (2x) वाला आँकड़ा कहाँ से मिला। पिछले 10 सालों में, यह कमोबेश 1x ही रहा है। मोटे तौर पर, यह 1x ही रहा है। और हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। विकास दर भी, जैसा कि आप जानते हैं, असल विकास दर लगभग 7% है। जब कोई 'दोगुना' (2x) की बात करता है, तो वे 2011-12 से पहले के समय की बात होती है। पहले हमारी क्रेडिट विकास दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और आपने देखा ही होगा कि बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर इसका क्या असर पड़ा था। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि 'दोगुना' (2x) जैसा कोई आँकड़ा है जिस पर हमारी नज़र है। हम अर्थव्यवस्था के लिए किसी खास विकास दर का लक्ष्य तय नहीं करते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें ज्यादातर अर्थव्यवस्था की संरचना पर निर्भर करती हैं। मौद्रिक नीति की भूमिका सिर्फ़ कम समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं। हम अर्थव्यवस्था की विकास दर को, और साथ ही क्रेडिट की विकास दर को, अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं।

हमसिनी कार्तिक:

धन्यवाद, सर।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब हम इस तरफ से कुछ सवाल लेंगे। मैं इकॉनॉमिक टाइम्स की संगीता मेहता से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगी।

संगीता मेहता, इकॉनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद, सर। सर, नीति वक्तव्य में आपने कहा है कि विकास में कुछ नरमी आने की उम्मीद है। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि आपको विकास में नरमी की उम्मीद क्यों है? और आपने आकांक्षा वाले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, तो मेरा दूसरा सवाल भी वही था?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, हम उन सभी उच्च आवृत्ति वाले संकेतक के आधार पर चल रहे हैं जिन्हें हम ट्रैक करते हैं। इसलिए, इसी आधार पर हमें लगता है कि एच1 में जो विकास लगभग 8% रही है, वह अब उसी स्तर की नहीं रहेगी। हमने इस तिमाही और आगे के लिए

अपने आँकड़े पहले ही जारी कर दिए हैं। अगर आप अलग-अलग क्षेत्र को देखें, तो मेरे पास अभी उनकी ब्योरा नहीं हैं, लेकिन हम आपको अलग से वे ब्योरा दे सकते हैं कि कौन से क्षेत्र शायद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, जितना उन्होंने ऐतिहासिक रूप से या अतीत में किया था। क्या आपके पास कुछ आँकड़े हैं जिन्हें आप यहाँ जोड़ना चाहेंगे?

पूनम गुप्ता:

मुझे लगता है कि मुख्य बात जो मैं जोड़ सकती हूँ, वह यह है कि आधार प्रभाव भी अपना असर दिखाएँगे। आप जानते हैं, अभी विकास दर बहुत, बहुत ज्यादा है। इसलिए, जब कोई नरमी की बात कर रहा है, तो वह इन्हीं बहुत ऊँचे स्तरों से है। क्षेत्र के हिसाब से, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र का आउटलुक बहुत मज़बूत है। इसलिए, जिस थोड़ी सी नरमी की हम बात कर रहे हैं, वह मुख्य रूप से आधार प्रभावके आधार पर सभी क्षेत्र में बँट जाएगी।

संजय मल्होत्रा:

और इसका कुछ हिस्सा निर्यात से भी जुड़ा है। इसलिए, हमने पहले ऊँचे टैरिफ़ की वजह से विकास दर कम कर दिए थे। तो, वे सभी क्षेत्र जिन पर टैरिफ़ का असर पड़ा है, जैसे टेक्सटाइल्स, चर्म उद्योग, कुछ हद तक जेम्स, ज्वेलरी, श्रिम्प्स - ये क्षेत्र निश्चित रूप से, हालाँकि हमारी कुल अर्थव्यवस्था में इनका हिस्सा बहुत छोटा है, फिर भी इन पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर और धन्यवाद, मैडम। अब मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड से मनोजित साहा से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा।

मनोजित साहा, बिज़नेस स्टैंडर्ड:

नमस्कार सर। आपने इस नीति में विकास को समर्थन देने की गुंजाइश का उल्लेख नहीं किया है। जबकि पिछली नीति में इसका उल्लेख किया गया था। तो, वास्तविक दर के नज़रिए से - जो आरबीआई की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 से 1.9 के बीच है - क्या वास्तविक दर के नज़रिए से कोई गुंजाइश है? और मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या आज के फ़ैसले के पीछे की सोच में यह भी शामिल था कि यूएस के साथ कोई व्यापार सौदा नहीं होगा? क्या यह भी एक वजह थी - हालाँकि इसकी संभावना बहुत कम है...

संजय मल्होत्रा:

नहीं, यह कोई वजह नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू माँग पर आधारित है, और टैरिफ़ - यानी ऊँचे टैरिफ़ - का जो भी असर है, उसे हमने अपने अनुमानों में पहले ही शामिल कर लिया है। इसलिए, यह ऊँचे टैरिफ़ की वजह से नहीं है। हम सभी चीज़ों को समग्र रूप से देखते हैं। गुंजाइश की बात करें, तो जैसा कि मैंने फिर से बताया, यह आगे चलकर हालात पर निर्भर करेगा। यह डेटा पर आधारित होगा कि क्या आगे और ज़रूरत या गुंजाइश है। सबसे पहले, गुंजाइश और फिर यह कि क्या इसकी ज़रूरत है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आगे चलकर, हमें कम महंगाई की उम्मीद है। और इसलिए, अगर महंगाई इसी तरह बनी रहती है, तो हमें उम्मीद है कि दरें - नीति दरें - कम रहेंगी, ज़्यादा नहीं। दर कितनी होगी, यह तो अटकलों का विषय होगा। लेकिन आगे चलकर, हमें कम महंगाई की उम्मीद है, और इसलिए हम ज़्यादा नीति रेपो दरों के बजाय कम नीति रेपो दरों की उम्मीद करते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं एनडीटीवी प्रॉफिट के विश्वनाथ नायर को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:

नमस्कार, गवर्नर साहब। रुपये पर आपने जो टिप्पणियाँ कीं - कि हम किसी खास स्तर को लक्ष्य नहीं बनाना चाहते, बल्कि जब उतार-चढ़ाव हो तब दखल देंगे - क्या दखल देने की वह सीमा अब बदल गई है? यानी, क्या उतार-चढ़ाव का कोई ऐसा बिंदु है जहाँ आप कहते हैं कि, ठीक है, इतना उतार-चढ़ाव तो ठीक है क्योंकि इसमें बाज़ार की ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर हम दखल देंगे? और इसका दूसरा हिस्सा यह है कि ऐतिहासिक रूप से कम महंगाई और ज़बरदस्त आर्थिक विकास का असर ज़मीनी स्तर पर महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह तालमेल की कमी कहाँ है - कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को न तो महंगाई में उतनी कमी महसूस हो रही है, और न ही उन्हें विकास की गति उतनी तेज़ लग रही है जितनी कि वह असल में है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि हम तो उन्हीं आँकड़ों पर भरोसा करते हैं जो जारी किए जाते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी विकास हो रही है। महँगाई निश्चित रूप से बहुत कम है। और खासकर अगर आप कीमती धातुओं को हटा दें, तो मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। बेशक, ऐसा हो सकता है - क्योंकि इसका भौगोलिक वितरण अलग-अलग है - कि कुछ राज्यों में महँगाई कम हो और कुछ राज्यों में ज़्यादा। फिर, समाज के अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों की उपभोग की टोकरी भी अलग-अलग होती है। इसलिए, अनुभव अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर महँगाई निश्चित रूप से कम हुई है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें, तो यह पहले लगभग 7% और 5% हुआ करती थी, और अब यह उससे भी काफी कम है। तो, महँगाई कम हुई है। विकास की बात करें तो - अगर आप लोगों के जीवन स्तर में आए सुधार को देखें - तो निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में इसमें सुधार हुआ है। इसलिए, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीनी स्तर पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। यह बहुत मुश्किल है - आपके पहले सवाल के जवाब में कहूँ तो - यह तय करने का कोई फ़ॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल है कि यह कैसे होता है... यह विज्ञान से ज़्यादा एक कला है। तो, प्रबंधन करते समय हम यही करने की कोशिश करते हैं।

विश्वनाथ नायर:

क्या विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा बाज़ार) में उतार-चढ़ाव को लेकर आपकी सहनशीलता बढ़ी है?

संजय मल्होत्रा:

मेरे लिए, यह वैसी ही बनी हुई है, और मुझे लगता है कि आरबीआई के लिए भी - मुझे इसमें कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता। हमें यह देखना होगा कि - कोई भी पीछे जाकर आँकड़े देख सकता है और खुद हिसाब लगा सकता है कि क्या उतार-चढ़ाव बढ़ा है - आँकड़े मौजूद हैं; कोई भी हिसाब लगा सकता है कि उतार-चढ़ाव कितना रहा है। और आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या उतार-चढ़ाव का इंडेक्स (जैसे VIX या आप जो भी पैमाना इस्तेमाल करते हैं) - आप उसका हिसाब लगाकर यह पता लगा सकते हैं कि क्या पिछले कुछ सालों में उतार-चढ़ाव असल में बढ़ा है या घटा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि उतार-चढ़ाव के प्रति हमारी सहनशीलता को बदलने की कोई जान-बूझकर की गई कोशिश की गई है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं थॉमसन रॉयटर्स की स्वाति भाट शेट्टे से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूंगा।

स्वाति भाट शेट्टे, थॉमसन रॉयटर्स:

धन्यवाद, सर। गवर्नर साहब, आज आपने कई बार इस बात को दोहराया है कि महंगाई पर जो बुनियादी दबाव हैं, वे वास्तव में बहुत कम हैं। मैं बस यह समझना चाहती थी कि ये कारक कौन से हैं? मेरा मतलब है, हाँ, खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, कीमती धातुएँ भी, जैसा कि आपने जिक्र किया; लेकिन क्या शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं की मांग भी नहीं बढ़ रही है? क्या इसकी वजह से भी महंगाई कम बनी हुई है? और दूसरी बात, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है: क्या हमें चीन की 'ओवरकैपेसिटी' (उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन) का असर भी महसूस हो रहा है? यह असर दूसरी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिल रहा है। क्या आपको भारत में भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? और साथ ही, क्या इतनी कम महंगाई किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में एक अच्छी बात है? 0.25% का स्तर तो बहुत ही कम है। हम 2% के लक्ष्य से भी काफी नीचे चल रहे हैं। तो, क्या भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का यह स्तर सही है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, 0.2% महंगाई का सही स्तर नहीं है। हमारा लक्ष्य 4% है, और हम इसी तरह की महंगाई का स्तर हासिल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही, मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ 0.2% के आंकड़े पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें उतार-चढ़ाव तो होंगे ही। बाज़ारों में अस्थिरता रहेगी, चाहे वह फॉरेक्स मार्केट हो। हमें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। या चाहे वह सेंसेक्स हो, शेयर बाज़ार हों, या आम तौर पर कीमतें हों—यह अस्थिरता तो रहेगी ही। और इसके कुछ असर 'बेस इफ़ेक्ट' (आधार प्रभाव) की वजह से भी हैं। पहले, खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और अब, आधार प्रभावकी वजह से, यह कम लग रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा है, असल महंगाई निश्चित रूप से कम ही है, और इसीलिए हमने दर में कटौती की है।

स्वाति भाट:

सर, उपभोक्ता मांग और चीन से आ रहे डिफ्लेशनरी दबाव - क्या आप कृपया इस बारे में कुछ बता सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

हाँ, मेरा मतलब है, ये सभी चीज़ें - इनमें आपूर्ति और मांग, दोनों ही तरफ के कारक काम कर रहे हैं। और यह अलग-अलग क्षेत्र पर निर्भर करेगा। जैसे, अगर खाने-पीने की चीज़ों की बात करें, तो वहाँ सप्लाई से जुड़े कारक ज़्यादा हावी होते हैं। वहाँ मंग से जुड़े कारक उतने ज़्यादा असरदार नहीं होते। इसलिए, यह हर क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगा। इस बात का कोई एक जवाब नहीं हो सकता कि असर सिर्फ मांग की वजह से है या सिर्फ सप्लाई की वजह से, या फिर किसका असर ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यह मांग और आपूर्ति, दोनों ही कारकों का मिला-जुला असर है। और क्योंकि मांग से जुड़े कारक भी मौजूद हैं, इसीलिए हमने अपना रेपो दर कम किया है। हम मांग को और बढ़ावा देने के लिए 'ईजिंग साइकिल' (ब्याज दरें कम करने के दौर) में हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'हिंदू बिज़नेस लाइन' के पीयूष शुक्ला को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

पीयूष शुक्ला, हिंदू बिज़नेस लाइन:

हाँ, नमस्कार, गवर्नर साहब और उप गवर्नर महोदय। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल आपके दर कट से जुड़ा है। आपने ज़िक्र किया था कि इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बैंक एक मुश्किल स्थिति में फँस गए हैं, क्योंकि डिपॉज़िट विकास को लेकर मुकाबला बढ़ता जा रहा है। सीएएसए बनाने में भी एक चुनौती है। क्या आपको लगता है कि आज की दर कटौती से जमा दर भी कम होगी? यह तो पहला सवाल है।

दूसरा सवाल उस सालाना रिपोर्ट के बारे में है जो हाल ही में आई थी। उसमें सोने का ज़िक्र था - कि आरबीआई और ज़्यादा सोना वापस ला रहा है; पहली छमाही में लगभग 64 टन सोना भारत वापस लाया गया है। क्या विदेशों में रखे हुए भौतिक सोने को वापस लाने की कोई जान-बूझकर की जा रही कोशिश है? यह देखते हुए कि कुछ विदेशी देशों ने युद्ध की वजह से अपना सोना वापस मंगा लिया है, और कुछ देशों ने दूसरे देशों का सोना रोक रखा है। क्या आरबीआई की तरफ से दूसरे देशों में रखे हुए भौतिक सोने को वापस लाने की कोई जान-बूझकर की जा रही कोशिश है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

हम विविधता ला रहे हैं। अपना सारा सोना एक ही जगह रखना ठीक नहीं है। इसलिए, इस कदम के पीछे निश्चित रूप से विविधता की एक कोशिश है। आपका पहला सवाल क्या था, माफ़ करना?

पीयूष शुक्ला:

क्या आज दर में कटौती से...?

संजय मल्होत्रा:

जमाकर्ता। देखिए, हमें असल में असली ब्याज दरों पर ध्यान देना होगा। जब महंगाई इतनी कम है और आगे भी कम रहने वाली है, तो भले ही नाममात्र की ब्याज दरें कम लगें, लेकिन आज असली ब्याज दरें काफी ऊंची हैं। तो यह बात न सिर्फ कर्ज लेने वालों के लिए सच है, बल्कि बचत करने वालों के लिए भी। और इसलिए, हमें उम्मीद है कि आगे चलकर, खासकर इस रेपो दर में कटौती के बाद, जमा दरें कुछ हद तक कम होंगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हमारे पास बाईं ओर से फिर कुछ सवाल आएंगे। अब मैं जी बिज़नेस की एकता सूरी से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूंगा।

एकता सूरी, जी बिज़नेस:

शुभ दोपहर, सर। सर, मेरा एक सवाल है। हमने कई मंचों पर सुना है कि सेबी प्रमुख ने कहा है कि बैंकों को गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स(पण्य व्युत्पन्नी) का हिस्सा बनना चाहिए। तो, क्या आने वाले दिनों में बैंकिंग नियमों में कोई बदलाव होने वाला है? क्या यह संभव है? क्योंकि उन्होंने यह बात एक से ज़्यादा मंचों पर कही है। और दूसरी बात, विदेशी निवेश विदेशी बैंकों के ज़रिए आ रहा है। तो, क्या आपको लगता है कि पीएसयू बैंकों में एफडीआई की सीमा 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वहां विदेशी निवेश आए और पीएसयू बैंक भी ज़्यादा मज़बूती से आगे बढ़ें?

संजय मल्होत्रा:

आपका पहला सवाल किस बारे में है?

एकता सूरी:

क्या बैंक गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव्स(पण्य व्युत्पन्नी) में निवेश कर सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

जो प्रस्ताव सेबी ने भेजा है। वह प्रस्ताव अभी हाल ही में हमारे पास आया है। हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत,

बैंकों का ऐसी गतिविधियों में शामिल होना मना है। अभी इसकी अनुमति नहीं है। तो, कानून में संशोधन करने होंगे। यह सिर्फ एक नियामक मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, ऐसा ही एक प्रस्ताव पहले भी आया था। तब उसकी जांच की गई थी और उसे उचित नहीं माना गया था। क्या पिछले 8-9 सालों में हालात में कोई बदलाव आया है? हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लाभ-हानि का अध्ययन किए बिना आपको जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। यह प्रस्ताव अभी-अभी आया है। इसलिए, इस पर आपको कोई जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

एकता सूरी:

और पीएसयू बैंकों में एफडीआई की जो सीमा लगभग 20% है... क्योंकि निजी बैंकों में पैसा आ रहा है...

संजय मल्होत्रा:

यह मामला भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वे इसे 20% तक बढ़ाना उचित समझते हैं या नहीं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर टिप्पणी करना उचित होगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ स्वदेश के अनुराग शाह से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करता हूँ।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

धन्यवाद सर। सबसे पहले, बधाई हो सर, आप 1 साल पूरा कर रहे हैं। हमने 125 आधार अंक की कमी देखी है। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी यह जारी रहेगा। सर, मेरा सवाल एटी1 बॉन्ड से जुड़ा है...

संजय मल्होत्रा:

जमाकर्ताओं के लिए ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी और उधार देने वालों के लिए ब्याज दरें घटती रहेंगी।

अनुराग शाह:

जी सर।

संजय मल्होत्रा:

ऐसा होना चाहिए। बैंकों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

अनुराग शाह:

सर, मेरा सवाल एडिशनल टियर-1 बॉन्ड से जुड़ा है। आजकल एटी1 बॉन्ड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई सरकारी बैंकों ने एटी1 बॉन्ड में पैसा लगाया है। और कई निवेशक सामने आए हैं जिन्होंने शिकायत की है कि एक मामले में उनका पैसा शून्य हो गया है। और सर, हमने देखा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाइ(आईआरडीएआई) ने भी आरबीआई को एक चिट्ठी लिखी थी। इरडाइ(आईआरडीएआई) के प्रमुख ने कहा कि इस फैसले की वजह से जीवन बीमा कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। और इसमें आम लोगों का पैसा लगा था। तो, इस बारे में आरबीआई का क्या कहना है?

और आम निवेशक ने कई बार कहा है कि गलत तरीके से बेचने की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा-पूंजी खत्म हो गई है। और इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। और आरबीआई ने यह भी कहा था कि हम खुदरा निवेशकों के लिए एटीआई बॉन्ड से जुड़े कुछ दिशानिर्देश लाएंगे। और सर, गलत तरीके से बेचने का काम बैंकों के ज़रिए ही होता है। और एटीआई बॉन्ड के अलावा, हमने दूसरी चीज़ें भी देखी हैं। बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले क्रेडिट-लिंक्ड प्रोडक्ट्स, बंडल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा वगैरह। दुनिया भर के लगभग 38-40 देशों में इन्हें विनियमित किया जाता है या इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो, क्या आपको लगता है कि आरबीआई को भी इस पर विचार करना चाहिए? गलत तरीके से बेचना एक बड़ी चिंता का विषय है। आपने भी इस पर अपनी राय दी है। वित्त मंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। तो, क्या आम लोग भरोसा कर सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

बिल्कुल। जहाँ तक एटीआई1 बॉन्ड का सवाल है, यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इसलिए, जब मामला अभी भी लंबित है, तो इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसलिए, मैं इस बारे में कुछ भी कहना पसंद नहीं करूँगा।

लेकिन हमने मिस-सेलिंग(गलत तरीके से बेचना) के बारे में पहले भी ज़रूर बात की है। सभी विनियमित संस्थाओं और बैंकों के लिए निर्देश हैं। और जब हम पर्यवेक्षण विज़न के लिए जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। लेखा-परीक्षा की जाती

है। कि मिस-सेलिंग(गलत तरीके से बेचना) के संबंध में हमने जो भी नियम और विनियम बनाए हैं, जो जिम्मेदारी हमने तय की है, कि मिस-सेलिंग(गलत तरीके से बेचना) में, अगर बंडलिंग होती है - जैसा कि आपने कहा - तो उस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह हमारा लगातार प्रयास रहा है। और इसी तरह, जैसे बीमा के मामले में है, इरडाइ(आईआरडीएआई) भी नियम लेकर आया है, कि कम से कम तीन उत्पाद, तीन बीमा कंपनियाँ, वगैरह एक साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए, सभी विनियामक, विनियमित संस्थाओं के साथ मिलकर, आने वाले समय में हम अपने नियमों और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ताकि मिस-सेलिंग(गलत तरीके से बेचना) की शिकायतें, जो अभी भी कुछ जगहों पर होती हैं, कम हो सकें। और इस तरह, मिस-सेलिंग(गलत तरीके से बेचना) की जो भी घटनाएँ हमारे सामने आती हैं, उनके खिलाफ हम सबसे सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और हम ऐसा करना जारी रखेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं इंडियन एक्सप्रेस के हितेश व्यास को अपना सवाल पूछने के लिए बुलाऊँगा।

हितेश व्यास, इंडियन एक्सप्रेस:

नमस्ते सर, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात का कोई हिसाब लगाया गया है कि अगर रुपया ₹1 गिरता है, तो महँगाई पर क्या असर पड़ेगा? और वह आँकड़ा क्या होगा?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, हमारे पास अपने आँकड़े हैं। मुझे लगता है कि 5% की गिरावट से महँगाई लगभग 35 आधार अंक बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ, इससे निर्यात और जीडीपी विकास को भी लगभग 25 आधार अंक का फ़ायदा होता है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के बेन जोस को अपना सवाल पूछने के लिए बुलाऊँगा।

बेन जोस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:

हाँ, सर। मेरा सवाल फिर से महँगाई के असर पर ही है। क्या आपने इसे 60 आधार अंक कम किया है?

संजय मल्होत्रा:

क्षमा कीजिए क्या कहा आपने?

बेन जोस:

इस साल के लिए महँगाई का अनुमान 2% है।

संजय मल्होत्रा:

ठीक है।

बेन जोस:

क्या आपको उम्मीद है कि रुपया मज़बूत होगा? या आपने 2% के अनुमान में रुपये के असर को भी शामिल किया है—जैसे कि रुपया ₹90 पर हो? इस बारे में आपका क्या आकलन है?

संजय मल्होत्रा:

हाँ, हमने अपने अनुमानों में रुपये के मौजूदा स्तरों को शामिल किया है।

बेन जोस:

ठीक है, धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस के श्री महेश नायक से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा।

महेश नायक, फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस:

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। इससे पहले अप्रैल में, आपने बताया था कि आप एनडीटीएल के 1% के बराबर सिस्टम चलनिधि से संतुष्ट हैं। पिछली तिमाही में, हमने औसतन यह देखा है कि चलनिधि का स्तर उस सीमा से नीचे रहा है। क्या आप अभी भी इससे संतुष्ट हैं, या आपने अपना नज़रिया बदल लिया है? और अगर हाँ, तो कृपया समझाएँ। और अगर आप अभी भी उसी नज़रिया पर कायम हैं, तो क्या मार्च तक प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए आपके पास कोई अनुमान या आंतरिक दिशा-निर्देश हैं?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, जब तक मौद्रिक नीति का प्रसारण हो रहा है—खासकर ऐसे समय में जब यह हो रहा है—मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराएंगे ताकि मौद्रिक नीति का प्रसारण हो सके। इसीलिए यह थोड़ी बेसी है। यह ज़्यादा है। वरना, शायद आपको इतनी ज़्यादा चलनिधि की ज़रूरत न पड़े। शायद आप अभी जितनी

चलनिधि हम दे रहे हैं, उससे कम में भी काम चला सकते हैं—जो कि 1% के आस-पास नहीं है, बल्कि 0.6% से 1% या उसके आस-पास रही है। और कभी-कभी 1% से ऊपर भी चली जाती है।

मुझे लगता है कि इस लगभग ₹1.5 लाख (करोड़) के साथ, यह 1% से ऊपर चली जाएगी। तो यही वह रेंज है जिस पर हम नज़र रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सटीक संख्या से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए—0.5, 1 या 0.6। ज़रूरी बात यह है कि हम उतनी पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराएंगे जितनी बैंकों को रिज़र्व रखने के लिए ज़रूरी है। चलनिधि की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग रिज़र्व उपलब्ध कराने के लिए पड़ती है। सर्कुलेशन में मौजूद करेंसी की वजह से यह कम हो जाती है। क्योंकि जब आप करेंसी देते हैं, तो आप जमा ले लेते हैं। उस हद तक, जमा कम हो जाते हैं और करेंसी बढ़ जाती है। या जब आप विदेशी मुद्रा करते हैं—अगर आप डॉलर बेचते हैं—तो आप बैंकों से वे जमाराशियां लेते हैं। तो, उनकी चलनिधि—वह रकम जिसे वे बैंकिंग रिज़र्व के तौर पर रख सकते हैं—कम हो जाती है। या फिर, बैंकिंग रिज़र्व की ज़रूरतों में बदलाव की वजह से भी इसमें बदलाव आता है। ज़्यादा डिपॉज़िट वगैरह की वजह से बैंकिंग रिज़र्व की ज़रूरतों में बदलाव होता है। तो, बैंकिंग चलनिधि—अभी के हिसाब से—काफ़ी ज़्यादा है और हम पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना जारी रखेंगे। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं 1% वगैरह के किसी खास स्तर को लक्ष्य कर रहा हूँ। मैं बस प्रणाली को—बैंकिंग कम्युनिटी को—यह भरोसा दिला रहा हूँ कि पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध रहेगी। खासकर तब तक, जब तक हम उस दौर में हैं जब ब्याज़ दरें नीचे जानी हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हम इस तरफ से कुछ और सवाल लेंगे। अब मैं इन्फार्मिस्ट मीडिया के आर्यन खन्ना को अपना सवाल पूछने के लिए बुलाऊंगा।

आर्यन खन्ना, इन्फार्मिस्ट मीडिया:

धन्यवाद, सर। नमस्कार। गवर्नर साहब, आपने चलनिधि के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ कहा है। बस इसके कुछ बारीक पहलुओं पर बात करना चाहूंगा। नवंबर में, आरबीआई ने सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदे थे। मार्केट में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह उस समय सरकारी- प्रतिभूति(जी-सेक) की परोपक्वता से जुड़ा था। क्या आगे भी आरबीआई की यही नीति रहेगी? और क्या आप आने वाले ओएमओ में 15 साल से ज़्यादा लंबी अवधि वाले बॉन्ड शामिल करने पर भी विचार करेंगे—जो कि आमतौर पर इस साल अब तक आपकी तय सीमा रही है—या फिर क्या आप अपने ओएमओ में

राज्य बॉन्ड भी शामिल करना चाहेंगे? इसी से जुड़ा एक और सवाल, चलनिधि प्रबंधन ढांचे के बारे में: नए चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत अब तक सिर्फ एक ही 7-दिन की नीलामी हुई है। नए चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत अब 7-दिन का परिचालन ही मुख्य परिचालन है। तो, इस बारे में आगे के लिए आपकी क्या राय है?

संजय मल्होत्रा:

तो, चलिए मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। नए चलनिधि मैनेजमेंट में, हमारी मुख्य कोशिश यह है कि हम अपने परिचालन लक्ष्य –यानी डब्ल्यूएसीआर(भारित औसत मांग दर)–को नीति रेपो दर के बराबर बनाए रखें। इसलिए, चलनिधि की उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनका हम पहले से अनुमान लगाते हैं, हमारे पास अब नए चलनिधि फ्रेमवर्क में यह लचीलापन है कि हम 1-दिन का ओवरनाइट ऑपरेशन, या फिर 3-दिन या 7-दिन का ऑपरेशन कर सकें। और इसी के अनुसार, वीआआर और वीआआरआर परिचालन किए जाते हैं।

आपका पहला सवाल जी-सेक ओएमओ की अवधि से जुड़ा था, जो हम आगे करेंगे; इस बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा। यह बस कुछ ही घंटों की बात है। हम इसकी जानकारी जारी कर देंगे। तीसरी बात, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम अलग-अलग मैच्योरिटी पीरियड वाले सरकारी बॉन्ड की एक विविध और संतुलित सप्लाई दें - जिसमें अल्पावधि, मध्यावधि, और दीर्घावधि, तीनों तरह के बॉन्ड शामिल हों; यह सब अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों और उनकी माँग पर निर्भर करता है। पहले, साल के पहले छमाही में - और पिछले कुछ सालों में भी - औसत परिपक्वता अवधि निश्चित रूप से बढ़ा है। पहले छमाही में, शायद ज़्यादा परिपक्वता अवधि वाली जी-सेक की नीलामी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। लेकिन अब आगे चलकर, मुझे लगता है कि इसे कम कर दिया गया है। इसका कैलेंडर भी आपके पास आ चुका है। इसलिए, हम अर्थव्यवस्था की माँग के हिसाब से एक संतुलित मिश्रण उपलब्ध कराएँगे।

आर्यन खन्ना:

एसडीएल भी, क्या आप खरीदेंगे?

संजय मल्होत्रा:

एसडीएल हम नहीं खरीदेंगे।

आर्यन खन्ना:

मेरे सवाल का एक हिस्सा यह था कि शायद आरबीआई के पास जो बॉन्ड थे, उनकी मैच्योरिटी (परिपक्वता) को लेकर बाज़ार का क्या अनुमान है। क्या आप ऐसा करना जारी रखेंगे? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों की जगह नए बॉन्ड खरीदेंगे?

संजय मल्होत्रा:

हम अभी 1 लाख (करोड़ रुपये) की खरीद करेंगे।

आर्यन खन्ना:

ठीक है। जनवरी में एक और परिपक्वता है।

संजय मल्होत्रा:

आप समय से बहुत आगे की सोच रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि हम पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराएंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है—और मैंने अपने भाषण में यह बहुत साफ़ कर दिया है—कि हम ओएमओ मुख्य रूप से चलनिधि के कारणों से करते हैं, किसी और कारण से नहीं। इसका मुख्य कारण चलनिधि उपलब्ध कराना है, और मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर हम तय करते हैं कि किन प्रतिभूतियों को लक्ष्य करना है। आगे चलकर, यह फिर से इस बात पर निर्भर करेगा कि चलनिधि की ज़रूरतें क्या हैं, और फिर हम तय करेंगे कि हमें और ओएमओ करने की ज़रूरत है या नहीं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं दूरदर्शन की श्यामा मिश्रा से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूंगा।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

नमस्कार, सर। मेरा सवाल ऑनलाइन धोखाधड़ी पर है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इसे रोकने के कई तरीके हैं, लेकिन एक बार जब किसी व्यक्ति का पैसा डूब जाता है, तो इस बात की बहुत कम उम्मीद होती है कि उसे अपना पैसा वापस मिल पाएगा। भले ही वे बहुत जल्द शिकायत कर दें, फिर भी पैसा वापस पाना मुश्किल होता है। इस दिशा में, क्या आरबीआई कोई कड़े कदम उठा रहा है?

संजय मल्होत्रा:

सबसे पहले, यह एक गंभीर मुद्दा है। आपने जो मुद्दा उठाया है, वह बहुत ही प्रासंगिक और गंभीर है। आरबीआई धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई, बैंक, कानून लागू करने वाली संस्थाएं और गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। हमने जन जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बार जब धोखाधड़ी हो जाती है और पैसा डूब जाता है, तो उसका सिर्फ एक हिस्सा ही वापस मिल पाता है। इस मुद्दे पर अभी अदालतों में चर्चा चल रही है। कुछ फ़ैसले भी आए हैं। केरल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, जिसमें उन्होंने आरबीआई को कुछ निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने भी एक फ़ैसला दिया है, जिसमें उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए हैं। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

खास तौर पर इस मुद्दे पर कि जब धोखाधड़ी होती है और पैसा डूब जाता है, तो उसे वापस कैसे पाया जाए। आरबीआई, अदालत और गृह मंत्रालय को न सिर्फ धोखाधड़ी रोकने के लिए, बल्कि यह पक्का करने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए कि पैसा जल्द से जल्द वापस मिल जाए। यह आरबीआई, सरकार, उच्चतम न्यायालय और बैंकों के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सब मिलकर इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं मिंट की सुभाना शेख को अपना सवाल पूछने के लिए बुलाना चाहूँगा।

सुबहाना शेख, मिंट:

धन्यवाद। नमस्कार, गवर्नर साहब। सर, मैं यह पूछना चाहती थी कि सांकेतिक जीडीपी के बारे में हमारे अनुमान, रियल जीडीपी के अनुमानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक होते हैं। और अब तो आईएमएफ ने भी जीडीपी के डेटा की गुणवत्ता के मामले में भारत को 'सी' ग्रेड दिया है। इससे आरबीआई के आकलन पर क्या असर पड़ता है? आपका आकलन क्या कहता है? इससे आपका काम कितना मुश्किल हो जाता है? साथ ही, उन्होंने भारत की 'डी फ़ैक्टो' (वास्तविक) विनिमय व्यवस्था को भी एक स्थिर व्यवस्था से बदलकर 'क्रॉल-जैसी' (धीरे-धीरे बदलने वाली) व्यवस्था के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। इस पर आपकी क्या राय है? और सर, आखिर में मैं दरों के असर के बारे में एक बात पूछना चाहती थी: अगर अक्टूबर में नए कर्जों पर ब्याज दरें बढ़ी

हैं, तो इसका मतलब है कि बैंकिंग प्रणाली के ज़रिए दरों में कटौती का असर कम हुआ है। तो, दरों में नई कटौतियों के बाद, क्या आपको लगता है कि प्रसारण पर कोई असर पड़ेगा? साथ ही, बॉन्ड प्रतिफल में भी अपेक्षाकृत सुस्ती आई है। बॉन्ड प्रतिफल पर प्रसारण का उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। तो, इस बारे में आपकी क्या राय है कि आने वाले समय में यह स्थिति किस तरह बदलेगी?

संजय मल्होत्रा:

तो चलिए, मैं आपके पिछले दो सवालों और जीडीपी और एक्सचेंज दर पर आपके पहले दो सवालों को लेता हूँ; मैं अपनी उप गवर्नर को बुलाऊँगा। वह आईएमएफ और हमारे अनुमानों से ज़्यादा नियमित रूप से डील करती हैं। हालाँकि मेरा मानना है कि हमारे अनुमान-जीडीपी, महँगाई, खासकर जीडीपी जो जारी होती है, और सीपीआई जो MoSPI देता है-काफ़ी सटीक होते हैं। बेशक, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं यह सवाल-जिसमें 'क्रॉल-लाइक' (धीरे-धीरे बदलने वाली) विनिमय दर का मुद्दा भी शामिल है-उप गवर्नर पूनम गुप्ता के लिए छोड़ता हूँ। मैं आपके बाकी दो सवालों के जवाब दूँगा। आपने एक ही बार में तीन-चार सवाल पूछ लिए, जो कि बहुत होशियारी की बात है।

तो, जैसा कि आपने कहा, ब्याज़ दरें बढ़ गई हैं। जहाँ तक लेंडिंग (कर्ज़ देने) की बात है, मुझे लगता है कि आप पिछले दो महीनों के डेटा की तुलना कर रहे हैं। तो, जैसा कि मैंने आज अपने वक्तव्य में भी समझाया, ब्याज़ दर का असर अब 79 आधार अंक का है। लेकिन अगर ज़्यादा ब्याज़ दर वाले कर्ज़ों का अनुपात बढ़ जाता है-उदाहरण के लिए, खुदरा ऋण जो अरक्षित (बिना किसी गारंटी के) होते हैं, या स्वर्ण ऋण-तो औसत ब्याज़ दर बढ़ जाती है। आप जानते ही हैं कि स्वर्ण- ऋण पर ब्याज़ दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर ऐसे कर्ज़ों का अनुपात बढ़ता है, तो औसत ब्याज़ दर भी बढ़ जाती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ब्याज़ दरों का असर धीमा पड़ गया है, ठीक है?

सुबहाना शेख:

ठीक है।

संजय मल्होत्रा:

ब्याज़ दरें-तो इसीलिए, आप जानते हैं, हम अब जो डेटा दे रहे हैं-आपके लिए जो आँकड़ा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वह असल में 'ब्याज़ दर का असर' है; यानी, क्या कर्ज़ की अलग-अलग श्रेणियों में ब्याज़ दरें नीचे आई हैं या नहीं। लेकिन सभी श्रेणियों में ब्याज़ दरें एक जैसी नहीं होतीं। आवास ऋण पर ब्याज़ दर 7.5% या 8% जितनी

कम हो सकती हैं, जबकि कुछ अरक्षित ऋण पर यह काफी ज़्यादा—10-11% तक—हो सकती है। अगर भविष्य में ऐसे कर्ज़ों का हिस्सा बढ़ता है, तो औसत ब्याज़ दर भी बढ़ जाती है—भले ही कर्ज़ की हर एक श्रेणी में ब्याज़ दरें नीचे ही आई हों। मुझे उम्मीद है कि मैं यह बात आपको ठीक से समझा पाया हूँ।

सुबहाना शेख:

जी सर, जी।

संजय मल्होत्रा:

दूसरी बात, बॉन्ड प्रतिफल की। इस पर बहुत, बहुत लंबे समय से सभी का ध्यान रहा है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, वह हमारा परिचालन लक्ष्य है, और फिर यह अन्य कई ब्याज दरों पर भी असर डालता है, जिसमें आपकी बॉन्ड प्रतिफल भी शामिल हैं। अगर आप अभी की बॉन्ड प्रतिफल की तुलना पहले की बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड्स से करें, तो वे लगभग एक जैसी ही हैं। वे - स्प्रेड्स ज़्यादा नहीं हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब नीति रेपो दर कम होगा, तो स्प्रेड ज़्यादा होगा। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जो स्प्रेड 6.50 पर था, 10 साल के बॉन्ड के लिए वही स्प्रेड 5.50 या 5.25 पर भी हो। तो - लेकिन ऐतिहासिक रूप से, अगर आप देखें कि स्प्रेड्स क्या थे, जब हमारा रेपो दर 5.5, 5.2, 5.15, 5, वगैरह था, तो आज की बॉन्ड प्रतिफल या आज के स्प्रेड्स बहुत अलग नहीं हैं। हो सकता है कि औसतन वे पहले की तुलना में कम रहे हों। यह एक बात है जिसे मैं सभी के सामने साफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि यह बात बार-बार सामने आती रहती है। शायद, आप जानते हैं, यह सवाल इसलिए बार-बार उठता है क्योंकि वे बहुत नीचे चले गए थे - लगभग 6.25 या उससे भी नीचे, या 6.15, 6.17 तक। लता के पास सारे आँकड़े हैं। तो, वे नीचे चले गए थे। वे नीचे क्यों गए, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बैठकर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका एक मुख्य कारण यह था कि उस समय हमने बहुत सारे ओएमओ किए थे। और इसलिए, आखिरकार, दिन के अंत में, यह माँग और आपूर्ति का ही मामला है। बेशक, यह आपकी नीति दर के लंबे समय के रास्ते के बारे में आपकी उम्मीदों पर भी निर्भर करता है। बेशक, यह एक उम्मीद है। यह एक कारक है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि मुख्य रूप से, आखिरकार, दिन के अंत में, यह माँग और आपूर्ति ही होगी।

और इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इन ओएमओ के ज़रिए अतिरिक्त सप्लाई पैदा की थी, जिससे कीमतें नीचे आ गईं; मुझे लगता है कि शायद वे सामान्य स्तर से भी नीचे चली गई थीं। मेरा मतलब है, समय के साथ बदली हुई दूसरी चीज़ों के अलावा,

यह भी एक वजह हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ़ यही एक वजह है। हाँ, उप गवर्नर गुप्ता।

पूनम गुप्ता:

धन्यवाद। उन दोनों सवालों को एक साथ पूछने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले, डेटा की क्वालिटी से जुड़े मुद्दे पर बात करते हैं। हम आईएमएफ के साथ 'आर्टिकल IV' के तहत सलाह-मशविरे के लिए तो जुड़ते ही हैं, साथ ही पूरे साल भी उनके संपर्क में रहते हैं। हमारे आँकड़ों की क्वालिटी को लेकर वे जो बात कह रहे हैं, वह बहुत ही सीमित दायरे में है। उनका वर्गीकरण टैक्सोनामी इस बात पर आधारित है कि क्या आईएमएफ को दिए गए डेटा में कुछ कमियाँ हैं, जिनसे निगरानी में रुकावट आती है। यह डेटा की क्वालिटी के बारे में नहीं है, बल्कि उन कमियों के बारे में है जिनसे निगरानी में दिक्कत आती है। और फिर, इसी पैमाने के आधार पर उन्होंने भारत के कई डेटा सीरीज़ की जाँच की—जैसे कि महँगाई, IIP (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक), राजकोषीय खाते और राष्ट्रीय खाते। अपने वर्गीकरण के हिसाब से, उन्होंने ज़्यादातर सीरीज़ को 'ए' या 'बी' श्रेणी में रखा, और सिर्फ़ राष्ट्रीय खातों को 'सी' श्रेणी में। और जब आप उनके फुटनोट्स (टिप्पणियों) को और गहराई से देखते हैं, तो पता चलता है कि यह 'आधार वर्ष' में बदलाव से जुड़ा मामला है। यह डेटा की गुणवत्ता के बारे में नहीं है। यह जारी किए गए आँकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में भी नहीं है। यह उस 'आधार वर्ष' के बारे में है, जिसे पुराना या अप्रचलित माना जा रहा था। इस बदलाव के बाद, मुझे लगता है कि वे इस मामले में संतुष्ट हो जाएँगे।

अब बात करते हैं विनिमय दर की। तो एक बार फिर, आईएमएफ और दूसरे संस्थान विनिमय दर प्रणालियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बाँटते हैं: स्थिर, अस्थिर, और नियंत्रित

अस्थिर। फ़िलहाल, बहुत कम देशों में ही स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू है। ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'पूरी तरह अस्थिर' प्रणाली है, जबकि सभी उभरते बाज़ारों में 'अस्थिर' प्रणाली के ही अलग-अलग रूप—यानी 'नियंत्रित अस्थिर' प्रणाली—प्रचलन में हैं। और भारत भी इसी प्रणाली का पालन करता है। अब, 'मैनेज्ड फ़्लोट' के दायरे में—जिसका मतलब है कि आरबीआई एक उचित स्तर के दोनों ओर होने वाले बेवजह के उतार-चढ़ाव को रोकने की कोशिश करता है—आईएमएफ ने पिछले 6 महीनों के डेटा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह उतार-चढ़ाव एक ऐसी सीमा के भीतर सीमित था, जो उनके हिसाब से सही थी; और इसी आधार पर, उन्होंने इसका एक उप-वर्गीकरण किया, जिसे 'क्रॉलिंग पेग' कहा जाता है।

फिर से कहूँगा कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दूँगा। यह बस अलग-अलग देशों के बीच की गई एक तुलना पर आधारित है—कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कितना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। असलियत तो यही है कि भारत की व्यवस्था 'मैनेज्ड फ़्लोट' वाली है, ठीक वैसे ही जैसे ज़्यादातर उभरते हुए बाज़ारों की होती है।

सुबहाना शेख:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर; और धन्यवाद, मैडम। अब मैं 'फ़ाइनेंशियल टाइम्स' के कृष्ण कौशिक से अनुरोध करूँगा कि वे अपना प्रश्न पूछें।

कृष्ण कौशिक, फ़ाइनेंशियल टाइम्स:

बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न रुपये के प्रबंधन से जुड़ा था, लेकिन सर, उसका जवाब तो मिल ही गया है।

संजय मल्होत्रा:

ठीक है, बहुत बढ़िया।

ब्रिज राज:

अब हम बाईं ओर से कुछ सवाल लेंगे। अब मैं 'द हिंदू' के ललातेंदु मिश्रा को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

ललातेंदु मिश्रा, द हिंदू:

धन्यवाद, सर। धन्यवाद, गवर्नर साहब। टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, और क्या व्यापार राहत उपायों ने निर्यातकों की कुछ चिंताओं को दूर किया है? अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी कर सकें।

संजय मल्होत्रा:

तो, असर की बात करें तो, जैसा कि मैंने कहा—मुझे लगता है कि मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था—कि हमारा असर बहुत कम है। इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अधिकांशतः घरेलू माँग पर आधारित है। हाँ, कुछ क्षेत्र ज़रूर इससे प्रभावित हुए हैं। आप उन क्षेत्रों के बारे में जानते ही हैं। और हमने एक राहत पैकेज जारी किया है। भारत सरकार ने भी एक राहत पैकेज जारी किया है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अवसर है, और निर्यातकों ने पहले ही आगे देखना शुरू कर

दिया है—न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने कारोबार में विविधता भी ला रहे हैं, वगैरह। और आगे चलकर हम इस स्थिति से और भी मज़बूत होकर निकल पाएँगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'बिज़नेस टुडे' की रिद्धिमा भटनागर से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करता हूँ।

रिद्धिमा भटनागर, बिज़नेस टुडे:

धन्यवाद। गवर्नर साहब, मेरा आपसे यह सवाल है कि आरबीआई ने बिना किसी गारंटी वाले निजी ऋण को लेकर कुछ चिंताएँ जताई हैं। तो, अभी उन चिंताओं से निपटने के लिए कौन से संकेत या उपाय देखे जा रहे हैं? और क्या निजी ऋण खंड या खुदरा ऋण खंड में आरबीआई की ओर से कोई दखल या हस्तक्षेप होगा?

संजय मल्होत्रा:

मैं अपने उप गवर्नर, स्वामिनाथन से इस पर जवाब देने के लिए कहूँगा। मुझे लगता है कि वे इस मामले को मुझसे ज़्यादा करीब से देखते हैं।

रिद्धिमा भटनागर:

और मेरा दूसरा सवाल यह था कि रिटेल सीबीडीसी का काम अभी कैसा चल रहा है? मुझे पता है कि अभी इस पर बात करना शायद थोड़ा...

संजय मल्होत्रा: अगर आपको कोई एतराज़ न हो, तो मैं बाईं ओर बैठे अपने दूसरे उप गवर्नर, रबी शंकर से इस सवाल का जवाब देने के लिए कहूँगा।

स्वामिनाथन जे:

हाँ। किसी भी पोर्टफोलियो के मामले में हम जिन पैमानों पर नज़र रखते हैं, उनमें से एक है विकास—यानी साल-दर-साल विकास दर—और साथ ही दूसरे सेगमेंट्स के मुकाबले उसकी रिलेटिव विकास। जिस समय हमने अरक्षित लोन पर कुछ मैक्रो-प्रूडेंशियल उपाय किए थे, वह ऐसा समय था जब वह पोर्टफोलियो बाकी पोर्टफोलियो के मुकाबले लगभग दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहा था। अभी, जैसा कि आप जानते होंगे, कुल क्रेडिट विकास लगभग 11% है; बड़े उद्योगों में यह 10% है, होम लोन 11% की दर से बढ़ रहे हैं, पर्सनल लोन 14% की दर से बढ़ रहे हैं, और इसके भीतर भी विकास ज़्यादातर सिक्वोर्ड सेगमेंट्स—जैसे गोल्ड लोन या होम लोन—में देखी गई है। अरक्षित लोन में काफी कमी आई है।

इसलिए, इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे हमें कोई चिंता हो। हम पोर्टफोलियो में होने वाले स्लिपेज पर भी नज़र रखते हैं। हालाँकि सितंबर तिमाही में अरक्षित पोर्टफोलियो में लगभग 8 आधार अंक की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर खुरा ऋण में कोई गिरावट नहीं देखी गई है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि अरक्षित लोन-अगर आप खास तौर पर इनकी बात कर रहे हैं-तो ये कुल रिटेल बुक का 25% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। और पूरी बैंकिंग प्रणाली के क्रेडिट के प्रतिशत के तौर पर, यह लगभग 17% है।

इसलिए, यह कुछ आधार अंक की बात है; मामूली बढ़ोतरी चिंता का विषय नहीं है। इसलिए, इस समय किसी भी तरह के उपायों की कोई योजना नहीं है। और हम आने वाले डेटा पर लगातार नज़र रखते रहेंगे। और अगर कुछ कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी, तो हम दखल देंगे। लेकिन कम से कम मुझे तो इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है जिसमें किसी रेगुलेटरी दखल की ज़रूरत हो।

टी. रबी शंकर:

रिटेल सीबीडीसी अच्छी स्थिति में है। धन्यवाद। इस समय, इसके लगभग 80 लाख से कुछ ज़्यादा यूज़र्स हैं। ट्रांज़ैक्शन की संख्या लगभग ₹12 करोड़ तक पहुँच रही है। अगर मुझे ठीक से याद है, तो इसकी वैल्यू लगभग ₹28,000 करोड़ के आस-पास है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि हम सीबीडीसी के लिए एक अनोखा यूज़ केस या अनोखे यूज़ केस बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इस नज़रिए से, हम प्रोग्रामेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे कई प्रोग्रामेबल प्रयोग और प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं, खासकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं वगैरह के साथ-साथ बैंकों के खास प्रोडक्ट्स के तालमेल से। इनमें से बड़ी संख्या में प्रयोग अभी चल रहे हैं। आगे चलकर, हमें उम्मीद है कि इनमें से कुछ स्थिर हो जाएँगे और आम इस्तेमाल में आ जाएँगे, जिन्हें एक आम यूज़र आसानी से अपना लेगा। तो, हमारा मुख्य फोकस इसी पर है। दूसरा फोकस सीमा-पार व्यवस्थाओं को लागू करने पर है। तो कुल मिलाकर, यह हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।

पीयूष शुक्ला:

सर, यह 12 करोड़ की राशि मासिक है या दैनिक?

टी. रबी शंकर:

अब तक का।

रिद्धिमा भटनागर:

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आशीष अगाशे को अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

आशीष अगाशे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया:

धन्यवाद, सर। गवर्नर सर, आपके वक्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले और सुधारों से विकास प्रक्रिया को और गति मिल सकती है। इन और सुधारों से आरबीआई की क्या उम्मीदें हैं? यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है, सर, कि क्या नॉमिनल विकास के रास्ते पर कोई चर्चा हुई? एमपीसी इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य विकास वाले हिस्से को किस नज़रिए से देखती है, और क्या इसका आज के दर संबंधी फैसले पर कोई असर पड़ा?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। सरकार को जो कुछ भी करना है, वह पहले से ही कर रही है। हम अपना काम करते हैं, हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन सरकार ने खुद ही कई सुधार किए हैं, जिनमें से कुछ तो लागू भी हो चुके हैं - जैसे कि श्रमिक सुधार, जिसे हमने हाल ही में देखा। तो, यह बात उसी संदर्भ में थी। हमारी तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। तो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। आपका दूसरा सवाल नॉमिनल जीडीपी पर है। सामान्य जीडीपी...

मेरा मतलब है, हमारे लिए तो हम 'वास्तविक जीडीपी' ही देखते हैं, और हमने उसी पर ध्यान दिया है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'डेक्कन क्रॉनिकल' की फलकनाज़ सैयद से अपना सवाल पूछने का अनुरोध करूँगा।

फलकनाज़ सैयद, डेक्कन क्रॉनिकल:

नमस्कार गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, बिना दावे वाली जमाओं के स्टॉक को कम करने के लिए - जो कि लगभग ₹67,000 करोड़ है - आरबीआई ने एक 'तेज़ भुगतान योजना' शुरू की है, जिसके तहत बैंकों को इस स्टॉक को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले तीन महीनों में इस स्टॉक में कितनी कमी आई है?

संजय मल्होत्रा:

में उप गवर्नर शिरीष मुर्मू से इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करूँगा।

शिरीष चंद्र मुर्मू:

हम इन बिना दावे वाली जमाओं पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। साथ ही, सरकार ने भी एक अभियान चलाया है। और हमारी तरफ से भी हमने बैंकों को प्रोत्साहन दिया है। तो, इसका नतीजा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको कुछ आँकड़े दूँ, तो अक्टूबर महीने में डीईए फंड से बिना दावे वाली जमाओं में लगभग ₹760 करोड़ की कमी आई है। और अगर आप इसकी तुलना पिछले अनुभवों से करें, तो औसतन यह कमी लगभग ₹100 से ₹150 करोड़ के बीच रहती थी। तो, यह बदलाव साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और आगे चलकर, हमें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया में और भी तेज़ी आएगी, क्योंकि सरकार और आरबीआई - दोनों ही मिलकर इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं।

फलकनाज़ सैयद:

सर, माफ़ कीजिए, यह ₹100 और ₹150 करोड़ की रकम किस समय-सीमा के लिए है?

शिरीष चंद्र मुर्मू:

दावा न की गई रकम में हर महीने होने वाली कमी।

संजय मल्होत्रा:

मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हम एक पोर्टल पर भी काम कर रहे हैं - उस पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए। तो इससे खातों वगैरह की पहचान करने और दावा न की गई संपत्तियों को वापस पाने में भी और मदद मिलेगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हमारे दाईं ओर दो और मीडियाकर्मी मौजूद हैं। मैं दैनिक भास्कर से श्री भीम सिंह से अनुरोध करूँगा कि वे अपना सवाल पूछें।

भीम सिंह, दैनिक भास्कर:

हमारे लिए पहले महंगाई दर 0.25% थी और इस बार फिर से दरों में कटौती की गई है। तो, मेरा सवाल यह है कि आरबीआई महंगाई को कितना नीचे तक बर्दाश्त कर सकता है? क्या यह अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती नहीं है?

संजय मल्होत्रा:

हमारा लक्ष्य 4% है, और इसका दायरा 2-6% के बीच है। चूंकि महंगाई बहुत कम है, और आने वाले समय के लिए, हमने अनुमान लगाया है कि मुख्य अंतर्निहित महंगाई दर बहुत कम रहेगी। हमने अगले वर्ष के लिए यह अनुमान लगाया है कि मुख्य अंतर्निहित महंगाई दर 4% से कम रहेगी। इसलिए, हम चाहेंगे कि महंगाई दर लगभग 4% के आस-पास रहे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं आकाशवाणी से सी. प्रार्थना से अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल पूछें।

सी. प्रार्थना, आकाशवाणी:

धन्यवाद, सर। नमस्कार, गवर्नर साहब। कुछ ऑनलाइन लेंडिंग ऐप्स द्वारा ग्राहकों के डेटा के दुरुपयोग को लेकर कतिपय चिंताएँ हैं। क्या आरबीआई इस बारे में कुछ कर रहा है?

संजय मल्होत्रा:

मैं दो बातें बता सकता हूँ, और बाकी लोग उन हालिया उपायों के बारे में बता सकते हैं जो हमने उठाए हैं। पहली बात यह है कि अब हमारे पास डिजिटल लेंडिंग और बैंकों तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा डिजिटल माध्यमों के उपयोग के लिए पूरी तरह से नियम-कानून मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि हमने एक ऐप या स्टोर भी लॉन्च किया है, जो एक तरह से विनियमित संस्थाओं के विभिन्न ऐप्स को 'व्हाइटलिस्ट' (मान्यता प्राप्त सूची में शामिल) करता है। तो इससे लोगों को यह जानने में मदद मिलती है कि कौन से ऐप्स वास्तव में विनियमित हैं और कौन से नहीं। लेकिन अगर कोई और पहल भी है - तो मुझे लगता है कि ये दो मुख्य पहल हैं जो हमने हाल के दिनों में की हैं, और मुझे लगता है कि इनसे मदद मिली है। इन उपायों से मदद मिली है, और हम लगातार सतर्क रहेंगे, ताकि हमारी तरफ से आगे जो भी कदम उठाने की ज़रूरत हो, वे उठाए जा सकें। धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। आपकी अनुमति से, सर, अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। मैं आपको और हमारे शीर्ष प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने धैर्यपूर्वक सभी सवालों के जवाब दिए और इस बातचीत को इतना दिलचस्प और संवादपरक बनाया। मैं मीडिया के सभी सदस्यों को भी उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी के लिए आगे का दिन सुखद हो, ऐसी कामना करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।